(ख) गांवों में कितने व्यक्ति आवास की पर्याप्त सुविधाओं के बिना रह रहे हैं ;

(ग) उपयुक्त मकानों के बिना रहने वाले व्यक्तियों के लिए सस्ते मकानों तथा न्यूनतम सुविधाओं की कब तक व्यवस्था कर दी जायेगी; और

(घ) आगामी 5 वर्षों में वर्षवार ऐसे कितने मकानों का निर्माण किया जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) और (ख) इस बारे में फिलहाल कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 1971 की जनगणना में इस बारे में एकत्रित किए गए ब्यौरे की जांच में काफी समय लगेगा। तथापि, चौथी योजना (1969-74) के लिए आवास पर कार्यकारी दल ने, योजना के आरम्भ में देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की क्रमशः 119 लाख और 718 लाख एककों की कुल कमी का अनुमान लगाया था। ये आंकड़े इस मान्यता पर आधारित थे, कि प्रत्येक परिवार के पास उचित प्रकार का एक पक्का रहने योग्य रिहायशी एकक होना चाहिए तथा तदनुसार इसमें कच्चे तथा जीर्णावस्था के वे मकान शामिल हैं, जिनका बदला जाना अथवा पर्याप्त सुधार करना अपेक्षित है।

(ग) उपलब्ध सीमित साधनों, उन साधनों पर मांगों की प्राथमिकताओं तथा समस्या की विशालता को देखते हुए, इसके समाधान के लिए समय की कोई सीमा नहीं बताई जा सकती।

(घ) सामाजिक आवास और नगर-विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में 195.27 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल है। इस लागत से चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, लगभग 2,00,000 मकानों के निर्माण किए जाने की आशा है।

बिहार में कुष्ठ रोगियों को राहत देने के लिए सहायता

1495. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध जानकारी के अनुसार बिहार में कुष्ठ रोगियों की संख्या 2.8 लाख है जब कि राज्य कुष्ठ रोगी प्राधिकरण द्वारा हाल ही में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में उनकी संख्या 6.1 लाख है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य प्राधिकरण द्वारा किए गए सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए कुष्ठ रोगियों को राहत देने हेतु सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचनानुसार, बिहार में कुष्ठ रोगियों की संख्या 2.8 लाख है। यह संख्या 1963 में उपलब्ध मुख-विज्ञान (एपिडिमियोलाजिकल) आंकड़ों पर आधारित है। फिर भी राज्य सरकार के राज्य कुष्ठ अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ऐसे कुष्ठ रोगियों की संख्या 6.1 लाख है।

(ख) 1955 में बिहार में चलाए गए राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम के ढांचे के अन्तर्गत, घर-घर जाकर इलाज करने वाली चलती फिरती गाड़ी के आधार पर कुष्ठ रोगियों को चिकित्सीय राहत मुहैय्या करने के लिए पहले ही 22 कुष्ठ नियन्त्रण एककों तथा 10 सर्वेक्षण शिक्षा एवं उपचार केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, कुष्ठ क्षेत्र में इस काम के लिए तीन स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान भी दिया जा रहा है। अब तक 25 लाख लोग इसके अन्तर्गत आ गए हैं और राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम के उपर्युक्त तीनों संगठनों द्वारा 65679 मामले दर्ज किए गए है।

1971-72 में, राज्य सरकार को 2 कुष्ठ नियन्त्रण एककों, 5 सर्वेक्षण शिक्षा तथा उपचार केन्द्रों की स्थापना करने तथा एक पुराने सहायता प्राप्त केन्द्र को पूरे कुष्ठ नियंत्रण एकक के रूप में उन्नयन करने के लिए कह दिया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिए निर्धारित प्रतिमान के अनुसार राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

Central Aid for Road Development Plans for Delhi and New Delhi

1496. SHRI H. K. L. BHAGAT : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) the total amount given by the Central Government to the Delhi Municipal Corporation and New Delhi Municipal Committee in connection with the road development plans during the last three years ; and

(b) how much of this amount has been spent by each of these authorities in this connection as on the 1st May, 1971 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI D. P. CHATTOPADHYAYA) : (a) The following amounts have been given by the Central Government to the Delhi Municipal Corporation and New Delhi Municipal Committee in connection with road development plans during the last 3 years *i.e.* 1968-69 to 1970-71 :

	(*Rs. in lakhs*)
Delhi Municipal Corporation :	Rs. 374.50
New Delhi Municipal Committee:	Rs. 66.915

The Delhi Municipal Corporation has also reported that Delhi Administration released a sum of Rs. 17.25 lacs for plan roads in 1968-69 & 1969-70 out of the additional resource raised by the Administration.

	(*Rs. in lakhs*)
(b) Delhi Municipal Corporation.	Rs 385.16
New Delhi Municipal Committee.	Rs. 65.50

Provision of Sewage and Drainage Facilities for Trans-Yamuna Areas in Delhi

1497. SHRI H. K. L. BHAGAT : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state :

(a) whether there are any plans for the provision of sewage disposal and proper drainage facilities for the trans-Yamuna areas in Delhi ;

(b) since when these plans are pending ; and

(c) when they are likely to be implemented ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI D. P. CHATTOPADHYAYA) : (a) to (c) The exact position is being ascertained and the required information will be laid on the Table of the Sabha.

Development of Tripura Town

1498. SHRI BIREN DUTTA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether any scheme has been proposed by the Tripura Government for the development of Tripura Town, specially Agartala ; and

(b) if so, the nature of proposal ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) and (b) The Government of Tripura have prepared a development plan for Greater Agartala, with the help of the Town and Country Planning Organisation of the Government of Indian, to control and regulate future development of the town and its environs. The plan covers an area of approximately 16,340 acres, envisaged to accommodate a population of 3 lakhs by 1996. According to the plan, one lakh persons are to be accommodated in the existing Agartala town (between Haora river and Katakhal), another one lakh in Kunjban-Nandan Nagar Complex (north of Katakhal), and the remaining one lakh in areas south of Haora river in Jogindra Nagar, Champamura and Malya Nagar.